International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 04, October - December, 2020, pp.265-270

नगरीय शासन के विविध मुद्दे एवं प्रस्ताव – समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

डॉ. रंजना महावर*

प्रस्तावना

वर्तमान समय में भारत जैसे विकासशील देशों में नगरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। नगरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके विकास के साथ कई प्रकार की समस्याएँ भी आती है। नगरीकरण की प्रक्रिया का एक पहलू विकास व खुशहाली लाना या सुविधापूर्ण आरामदायक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के साधनों को बढ़ाना है तो वहीं दूसरा पहलू नकारात्मक रूप लिये हुये है जिसमें विकास के साथ–साथ विनाश अव्यवस्था, अपराध, असामाजिकता, अविश्वास व अराजकता भी बढ़ने लगी है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से नगरीय का अर्थ नगर में रहने वाले समुदाय से हैं। नगर क्षेत्र की अवधारणा स्पष्ट हो जाने के बाद नगरीय की समाजशास्त्री अवधारणा स्पष्ट की जा सकती है अर्थात् नगरीय शब्द का प्रथम स्थान है। यह समुदाय विशेष का सूचक शब्द है। सम्पूर्ण मानव समाज को किन्हीं लाक्षणिक आधारों पर नगरीय तथा ग्रामीण समुदायों में विभाजित किया जा सकता है जो नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। रोजगार के अवसर तथा नागरिक सुविधाओं के कारण भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। अत्यधिक जनसंख्या बोझ से नगरों में आर्थिक समस्याएँ, सामाजिक–सांस्कृतिक समस्याएँ पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं तथा अन्य कई समस्याएँ उत्पन्न होती है। भारत में नगरों से सम्बन्धित समस्याएँ निम्न है–

आर्थिक समस्याएँ

नगरों में आने वाली अधिकांश जनसंख्या अकुशल श्रमिकों की है। इससे वे रोजगार के उचित अवसर प्राप्त नहीं कर पाते और आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। इसके अलावा कार्य की बदलती प्रकृति के कारण बेरोजगारी बढ़ती है जिससे नगरों में आर्थिक समस्याओं में वृद्धि होती है।

पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ

नगरीय केन्द्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएँ उत्पन्न हो गई है। सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। अत्यधिक जनसंख्यां दबाव के कारण शहरी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग गन्दी बस्तियों में रहने के लिए अभिशप्त है। भारत में अधिकांश महानगरों के 25 प्रतिशत निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं।

जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग अत्यधिक तीव्र गति से होता है। इससे आज अधिकांश महानगर जल की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। दिनों दिन नगरों में पक्के आवासों की संख्या बढती जा रही है जिससे वर्षा का जल रिसकर अन्दर नहीं जा पाता है। फलस्वरूप धरातलीय जल–स्तर में कमी आ रही है। इसके अलावा अवैध बस्तियों में स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव के कारण नगरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। इसके अलावा परिवहन के साधनों का अत्यधिक प्रयोग शहरों में ध्वनि तथा वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं में वृद्धि होती है। महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी काफी ऊँचा हो गया है। इनमें अबाध गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण स्वचालित वाहनों तथा अन्य ध्वनि प्रदूषणों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत के अधिकांश महानगरों में ध्वनि का स्तर 70–80 डेसीबल तक पहुंच गया है जिससे श्रवण सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न हो गई है।

---

6 पी.डी.एफ. (आई.सी.एस.एस.आर.), समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

आवास की समस्या

पर्यावरण के बाद सबसे महत्वपूर्ण समस्या आवास की है। यह समस्या आवास की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में भारत में 3 करोड़ 10 लाख आवासीय इकाइयों की कमी है जिसमें 206 लाख आवास की कमी ग्रामीण क्षेत्र में तथा 104 लाख शहरी क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण सुविधायुक्त मकानों की मात्रा भी काफी कम है तथा सन् 2020 तक लगभग 7 मिलियन आवासों की कमी की सम्भावना है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार कुल नगरीय आबादी का 14.68 प्रतिशत झुग्गी–झोपडियों में निवास करता है। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है।

रोजगार की समस्या

जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। गांवों से शहरों में आने वाले लोगों की अधिक संख्या के कारण उन्हें शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती चली जाती है।

निर्धनता

निर्धनता सार्वभौमिक समस्या है। भारत में निर्धनता मुख्य रूप से हमारी परम्परागत सामाजिक संरचना का परिणाम है। निर्धनता का सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के अभावों से होने के साथ ही सामाजिक अभाव से भी है। सभी विभिन्न स्तर के लोगों के लिए निर्धनता का स्तर अलग–अलग हो सकता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न होना ही निर्धनता है। इसे एक सापेक्षिक स्थिति भी कहते हैं। नगरों में कई श्रमिक ऐसे होते हैं जिनको यदि नियमित रोजगार प्राप्त न हो तो भोजन प्राप्ति में भी मुश्किल आती है। नगर व ग्रामों में गरीबी का प्रतिशत के आधार पर समग्र आंकलन किया जाए तो नगरों में विपन्नता अधिक पायी जाती है। वहाँ सम्पन्नता और विपन्नता में जो अन्तर प्राया जाता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है।

मलिन बस्तियाँ

भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। परन्तु इसके लिए पर्याप्त रूप से नीतियाँ नहीं बनाई गई है। प्रतिदिन हजारों लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। अधिकांशतः रोजगार की तलाश और गरीबी से उभरने के लिए गांवों से पलायन करने वाले समृद्ध शहरों की तरफ ही रूख करते हैं। इनमें से अधिकत्तर शहरों की मलिन बस्तियों में रहते हैं। ये साल दर साल रहते चले जाते हैं, परन्तु अपने लिए घर नहीं जुटा पाते। जो लोग इन मलिन बस्तियों में रहते हैं, वे बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं से वंचित है। अध्ययनों से पता चलता है कि गरीब व मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग कर्ज और सामाजिक आर्थिक ठहराव के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। यहाँ रहने वाले नरकीय जीवन गुजारने को मजबूर है। सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गन्दगी और जल भराव की ये समस्या हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार इनके जीवन स्तर में कभी सुधार नहीं हो पाता।

स्वास्थ्य समस्याएँ

नगरीय समाज की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता हैं भोजन, वस्त्र और आवास। पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वस्त्र तथा साफ सुथरा आवास मानव की कार्यक्षमता एवं जीवन को सुचारू रूप से सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम वांछनीय आवश्यकता है। वर्तमान युग मशीनीकरण का युग है। औद्योगिकरण के जितने भी आयाम है, सब मशीन पर निर्भर है, लेकिन इन मशीनों की कार्यक्षमता को बनाये रखने अथवा अनुकूल दशाओं के विकास के श्रमिकों का संतुलित एवं पौष्टिक आहार, शरीर ढकने को पर्याप्त वस्त्र और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्यकर आवास की उपलब्धि नितान्त आवश्यक है। लेकिन औद्योगिक प्रगति के बाद आज स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था अच्छी नहीं है।

निरक्षरता

भारत में निरक्षरता का प्रतिशत चिंताजनक है। भारत में दस में से पाँच व्यक्ति निरक्षर हैं शहरों की तुलना में गांवों की हालत ज्यादा खराब है जबकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय स्थापित करवाए गये हैं, फिर भी समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। इसके अलावा केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से निरक्षरता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में बहुत से वयस्क भी निरक्षर है।

शिक्षा व्यवस्था

भारत की शिक्षा प्रणाली को दोषी ठहराया जाता है क्योंकि यह अब भी व्यावहारिक और कौशल आधारित न होकर सैद्धान्तिक है। छात्र–छात्राएँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हम इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। औपनिवेशक स्वामी द्वारा इस तथाकथित आधुनिक शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि छात्र नौकरी तो कर सके लेकिन किसी का नेतृत्व न कर सके। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए कई लेख लिखे थे और सुझावों को प्रस्तुत किया था लेकिन सफलता अभी भी हमेशा की तरह एक दिखावा है।

महिला सुरक्षा

पुरूष और महिला दोनों ही समान अवसरों का आनन्द लेते हैं, लेकिन जब बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की तो इस मामले में भारत बहुत पीछे है। घरेलू हिंसा, बलात्कार के मामले, मीडिया में महिलाओं का चित्रण आदि जैसे मुद्दों पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

बुनियादी ढांचा

भारत को अपने बुनियादी ढांचे जैसे बेहतर सड़के, पानी और स्वच्छता आदि सेवाओं पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है।

सामाजिक–सांस्कृतिक समस्याएँ

नगरों की एक बड़ी समस्या सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या है। वास्तव में नगरों में विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न–2 समुदायों के लोग आते हैं जिनके रीति–रिवाज, भाषा तथा धार्मिक विश्वास एक दूसरे से अलग होते हैं। यह विविधता आर्थिक एवं राजनैतिक कारणों से सामाजिक विभेद उत्पन्न करती है। इसके अलावा शहरों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं के महंगे होने के कारण कमजोर वर्ग के लोग अच्छी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली जनसंख्या में पुरूषों की अधिकता के कारण नगरों की जनसंख्या का लैंगिक अनुपात भी असंतुलित हो जाता है। आर्थिक अभाव, परिवार से दूरी तथा उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के कारण शहरों में सामाजिक अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है।

यातायात की समस्या

प्रत्येक शहर में बेतरहीब यातायात एक गम्भीर समस्या बन गया है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। शहर में रहने वाले समृद्ध लोग अपनी शक्ति और सम्पन्नता के प्रदर्शन के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं।

नगरीकरण एवं कच्ची बस्ती की महिलाओं की समस्याएँ –

नगरीकरण और औद्योगिकरण में गहरा सम्बन्ध है। नगरीय विकास औद्योगिकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही सम्भव है। रोजगार की तलाश में गांवों से पलायन कर शहरों में आने के कारण नगरों में कच्ची बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कच्ची बस्तियों में निम्न आवासीय दशाओं जैसे प्रकाश एवं धूप का अभाव, घर के निकट जल भराव की स्थिति, घरों में रोशनदान एवं खिड़की का अभाव, कमरों के छतों की कम ऊँचाई, छोटे कमरों में अत्यधिक भीड़, टिन एवं पॉलीथिन की छतें, धुएँ का निकास न होना, घरों के समीप कूडा–कचरे का जमाव एवं दुर्गन्धयुक्त गन्दी नाली का प्रभाव उनमें निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर अधिक दृष्टिगत होना है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी कार्यक्षमता,

प्रजननतन्त्र बच्चों के पालन–पोषण, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। कच्ची बस्तियों की महिलाओं का जीवन शारीरिक मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के कारण नारकीय बना हुआ है । नगरीकरण के कारण कौनसी समस्याएँ पैदा हो रही है?

नगरीकरण से जुड़ी मुख्य समस्याओं में शामिल है–

- शहरी फैलाव
- आवास और मलिन बस्तियों का विस्तार
- भीड़ और व्यक्तिवाद की भावना।
- पानी की आपूर्ति और जल निकासी का बेहतर न होना
- शहरी बाढ
- परिवहन और यातायात की समस्या
- बिजली की कमी
- प्रदूषण
- शहरी ग्रीष्मदीप प्रभाव
- अपराध और बाल अपराध
- भीख
- शराब और ड्रग्स की समस्या
- भ्रष्टाचार

नगरीकरण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय –

- स्मार्ट सिटी मिशन
- स्वच्छ भारत अभियान
- हेरिटेज सिटी डेवलपमेन्ट एंड ऑग्मेटेशन योजना यानी ह्रदय
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- कायाकल्प और शहरी रूपान्तरण के लिए अटल मिशन यानी अमृत योजना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)
- राजीव आवास योजना

भारत में नगरीय शासन खराब क्यों है?

- वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव
- पैसों की कमी
- जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव
- विभिन्न एजेन्सियों (जैसे पानी, परिवहन आदि) के बीच बेहतर समन्वय का न होना
- समुचित शहरी विकास नीति का अभाव
- अनुचित शहरी नियोजन
- परियोजनाओं का खराब कार्यन्वयन

अन्य सामाजिक समस्याएँ

इन उपरोक्त मुख्य समस्याओं के अतिरिक्त भी कई समस्याएँ है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग अधिकतर गरीब होते हैं अतः पैसे की कमी के कारण वे अमीर लोगों की बस्तियों के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। इन गरीब वर्ग के लोगों का शैक्षणिक स्तर भी निम्न होता है तथा नगरों की साफ सफाई की व्यवस्था का बोझ नहीं होने के कारण शहरी वातावरण उनके लिए संकटमय हो जाता है। यह संकट कभी–कभी विकराल

रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के तौर पर जनवरी 1995 में दिल्ली की एक मध्यमवर्गीय कॉलोनी में गरीब लोगों के समूह ने वहाँ स्थित पार्क का उपयोग शौचालय के रूप में करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप उत्पन्न हुए झगड़े में चार लोगों की मृत्यु हो गई तथा जान–माल का काफी नुकसान हुआ। यहाँ पर स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी की यह उक्ति कि ''गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है'' काफी प्रासंगिक होती है। इसके अतिरिक्त गरीबी एवं अमीरी की बढ़ती हुई खाई के कारण गरीब लोगों में अधिकाधिक पैसे की प्राप्ति के लिए आपराधिक भावना भी पनप उठती है जिसमें शहरी जीवन तनावग्रस्त हो जाता है।

कुछ अन्य समस्याएँ

- हमारे देश का लगभग हर शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण ने शहरों में असमानता को जन्म दिया है।
- शहरों की सड़कों पर गड्डे, सीवर प्रणाली का अभाव एवं जल जमाव से होने वाली परेशानियाँ, बिजली, पानी एवं संचार सुविधाओं का अस्त–व्यस्त व असमान रूप शहरी जीवन को इतना अधिक समस्यामूलक बना देता है कि कई शहरों में जाने की कल्पना मात्र से सिहरन होने लगती है।
- अपराध की दृष्टि से भी शहर तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित है। कंक्रिट के जंगल में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते।
- भावना शून्यता, संवादहीनता और व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति शहरी जनसंख्या के जीवन का हिस्सा बन गई है।

नव उदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गांव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्ता बनकर रह गए है। शहर आधुनिकीकरण व उपभोक्तावादी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश गांव अपने अस्तित्व के लिए इन शहरों से जुड़े हुए है। शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं पलायन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और नई पीढ़ी गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगी है।

नगरीय शासन की इन समस्याओं के समाधान हेतु एकीकृत तथा नियोजित नीति बनाने की आवश्यकता है। शहरों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर वहाँ जनसंख्या में कमी लाई जा सकती है, वही जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करके शहरों में प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी प्रयास किए जाए तथा निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी बढ़ाना होगा। जनसंख्या को काबू में करना होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरण रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर– जैसे नेहरू रोजगार योजना, ट्राइसेम, आर.एल.ई.जी.पी. इत्यादि प्रदान किये हैं। इसके साथ–साथ नगरीय बाह्य क्षेत्र में विकास ध्रुव केन्द्र की स्थापना करनी होगी। नगरीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी बाह्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों को शहरों की तरफ पलायन से रोका जाए। ग्रामीणों को गांवों में ही अधिक रोजगार के अवसर दिये जाये। सरकार शहरी गरीबों को आवास के लिए सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाए। उसके कोई कर्मचारी मलिन बस्तियों में नहीं रहे इसके लिए आवास सुविधा दे। सरकार अस्पृश्यता और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर समस्या को काबू में लाए। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी प्रयास शुरू हो। सरकार द्वारा आवंटित धन का उचित सदुपयोग करवाया जाए। गली–गली और मौहल्लों में कचरा, कूडा–करकट व अपशिष्टों को उठाने के लिए स्वच्छता–मित्र एवं वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाए। नगरीय एवं ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के उपाय किये जाएँ जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, निर्धनता राहत कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण आवास अन्त्योदय योजना, स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना आदि कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के पैमानों को तय करना आवश्यक है और इस दिशा में स्वच्छता पर गहनता से विचार करना व अपना सहयोगी योगदान देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। जिससे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक व राष्ट्र की सम्पूर्ण सम्पदा की रक्षा की जा सके।

अन्य प्रयास

ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार पैदा करने के साथ–साथ पलायन को कम करने के लिए ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने की जरूरत है। इस मामले में मनरेगा ने गांवों से शहरी की ओर पलायन कम करने में अहम भूमिका निभाई है।

- PURA और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ... मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर देना होगा।
- शहरों की लोकल प्लानिंग और सार्वजनिक उपयोगिता के लिए स्टैण्डर्ड व्यवस्थाओं को विकसित किया जाना चाहिए।
- समावेशी शहरीकरण की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि शहरी गरीब और अन्य कमजोर समूहों की आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सम्मानजनक रोजगार और सुरक्षित वातावरण जैसी जरूरतें पूरी की जाएँ।
- पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरीकरण : शहरीकरण बेहतर प्रबन्धन, ग्रीन पैचेज का विकास, आर्द्रभूमि, उचित अपशिष्ट प्रबन्धन
- सार्वजनिक परिवहन में निवेश
- बेहतर ढांचागत सुविधाएँ – पानी, सीवरेज और बिजली सुनिश्चित करना।
- बेहतर अर्बन गवर्नेंस को सुनिश्चित करना इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं–
- राजकोषीय विकेन्द्रीकरण और पर्याप्त धन की उपलब्धता
- नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों का संचालन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- नागरिक भागीदारी

इन उपायों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करके ही हम इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- विलियम ए. राब्सन : इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, वाल्यूम 9–10, पृष्ठ– 574
- डॉ. सरोज बाला चोपडा : स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1993, पृ. 37
- डॉ. श्रीराम माहेश्वरी – भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1997–98, पृ. 193
- आचार्य दुर्गादास बसु – बृजकिशोर शर्मा : भारत का संविधान – एक परिचय प्रेंटिस – हाल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1998, पृ. 275
- इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, वाल्यूम–9–10, पृष्ठ संख्या 584
- विल्सन फेडरिक विलियम : सम इण्डियन प्राब्लम्स, राममोहन लाल इलाहाबाद, 1929, पृ. 46–55
- डब्ल्यू एच ओ रिपोर्ट : 12 जुलाई 2014, जेनेवा, न्यूयार्क
- यूनिसेफ रिपोर्ट : 2015
- यादव, साधना : कुरूक्षेत्र, मई 2015
- यू.एस. सेन्टर्स फॉर डिजीज कन्ट्रोल एण्ड प्रिवेंशन अटलांटा जी.ए. विश्व जल फोरम, मार्च 2006.

❖◆❖